राज्य सरकार भी बनाएगी आरओबी

राज्य ब्यूरो, पटना : अब राज्य सरकार भी रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज बनाएगी। अभी तक इसके निर्माण पर केंद्रीय एजेंसी इरकॉन का एकाधिकार था। ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार और रेलवे के बीच अब करार हो गया है। सरकार की इस पहल से अब आरओबी और अंडरपास का निर्माण तेज गति से हो सकेगा। मालूम हो कि राज्य में करीब 1380 रेलवे क्रॉसिंग हैं। कई ऐसी क्रॉसिंग हैं, जहां गाड़ियों की आवाजाही एक लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट से अधिक है। इसी श्रेणी के क्रॉसिंग पर आरओबी या आरयूबी बनाने का प्रावधान है। इस मानक के तहत फिलहाल 131 क्रॉसिंग पर इसकी जरूरत है। फिलहाल राज्य सरकार स्टेट हाइवे और मध्य श्रेणी की सड़कों पर अपने खर्च से आरओबी या आरयूबी का निर्माण करा रही है। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग होने पर इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है।

दो निगमों को मिली जिम्मेवारी : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को आरओबी या आरयूबी निर्माण की जिम्मेवारी दी गई है।

इसके लिए रेलवे से करार हो चुका है। राज्य और केंद्र सरकार इस पर आने वाली लागत का आधा-आधा खर्च वहन करेंगी। पथ निर्माण विभाग आरओबी या आरयूबी बनाने वाली क्रॉसिंग की पहचान करेगा। जमीन अधिग्रहण और एप्रोच रोड का निर्माण राज्य सरकार के जिम्मे रहेगा। लेकिन रेलवे पटरी के ऊपर बनने वाले ब्रिज की तकनीकी जांच रेलवे के अधिकारी करेंगे।

सहूलियत

- राज्य और रेलवे के बीच करार होने से आम लोगों को मिलेगी जाम से राहत
- अब तक इस पर केंद्रीय एजेंसी इरकॉन का था एकाधिकार

1380 रेलवे क्रॉसिंग हैं अभी पूरे राज्य में, अब इन पर तेजी से होगा काम

131 क्रॉसिंग पर आरओबी या आरयूबी बनाने की अभी है जरूरत

तीन जिलों में खर्च होंगे 107 करोड़ रुपये

वैशाली, सारण और बेतिया में आरओबी के लिए पथ निर्माण विभाग की पहल शुरू हो गई है। ये वैशाली के गोरौल रेलवे स्टेशन के समीप लेवल क्रासिंग संख्या 23 बी के निकट, सारण के गोल्डनगंज स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग संख्या 32सी के निकट और बेतिया छावनी की लेवल क्रॉसिंग संख्या दो के निकट बनेंगे। इन स्थानों पर ओवरब्रिज व पहुंच पथ निर्माण के लिए रेलवे ने 214 करोड़ 63 लाख का डीपीआर भेजा था। राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 107 करोड़ 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।